आज का दिन 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया।

बिजनेस

केंद्र ने कपड़ा कारोबारियों को राहत देते हुए निर्यात कर छूट का दायरा 2024 तक बढ़ाया

कर छूट मिलने से कपड़े का निर्यात सस्ता होगा

राहत

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

केंद्र सरकार ने कपड़ा कारोबारियों को राहत देते हुए निर्यात छूट का दायरा 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का आकलन है कि इस कदम से न सिर्फ कारोबारियों का निर्यात आठ फीसदी तक सस्ता होगा बल्कि उन्हें यूरोप और अमेरिका में खोए बाजार वापस मिल पाएंगे।

केंद्रीय टेक्सटाइल सचिव यू. पी. सिंह ने हिन्दुस्तान से खास बातचीत में बताया कि ये स्कीम दिसंबर 2020 में खत्म हो गई थी और लंबे समय से कारोबारियों की इसे फिर से शुरू करने की मांग थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब फिर से कारोबारी माहौल सुधरने लगा है और वैश्विक बाजारों में टेक्सटाइल उत्पादों और गारमेंट की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में दाम उंचे होने की वजह से भारतीय कारोबारियों को उतना फायदा नहीं हो पा रहा था।

बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के सस्ते माल की वजह से भी यहां के निर्यातकों को दिक्कत आ रही थी। कपड़ा निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट यानी आरओएससीटीएल योजना शुरू होने से एक बार फिर से निर्यातक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी खोई पकड़ वापस पा सकेंगे।

टेक्सटाइल सचिव के मुताबिक इस स्कीम से अलग अलग चीजों पर कारोबारियों को कम से कम तीन फीसदी और अधिक से अधिक आठ फीसदी फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से निर्यातकों को करीब 7 हजार करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है।

कपड़ा उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश

सिंह ने ये भी कहा कि पहले इसे निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट यानि आरओडीटीईपी स्कीम का हिस्सा बनाया जाना था। लेकिन ये छूट आरओएससीटीएल के मुकाबले कम थी इसीलिए सरकार ने इसे ही जारी रखने का फैसला लिया है। कपड़ा उद्योग में भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ वैश्विक बाजार में अपनी धाक भी जमा सके इसके लिए सरकार ने टैक्स छूट का दायरा लंबी अवधि के लिए बढ़ाया है। ये 1 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएगी और 31 मार्च 2024 तक चलेगी।

03% से 8 फीसदी तक सस्ता होगा कपड़ा का निर्यात करना कारोबारियों के लिए

07 हजार करोड़ रुपये का रिफंड मिल सकता है इस योजना से कारोबारियों को

2020 में पुरानी स्कीम खत्म हो गई थी जिसे बढ़ाया गया

लंबी अवधि की योजना बनाते हैं कारोबारी

यू. पी. सिंह के मुताबिक कपड़ा कारोबारी निर्यात के लिहाज लंबी तैयारी करनी होती है। वो न सिर्फ बाजार का आंकलन करते हैं बल्कि किसी देश की मांग के बारे में पूरी छानबीन करने के बाद ही अपनी यूनिट लगाते हैं। सरकार ने इसीलिए लंबी अवधि की छूट योजना बनाई है ताकि उन्हें कारोबार लगाने के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। निर्यात में राहत देने से सरकार की कोशिश देश में इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की भी है। आंकड़ों के मुताबिक कुल निर्यात में से 12 फीसदी से ज्यादा टेक्सटाइल से ही होता है। साथ ही ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं।

केंद्र ने राज्यों को 75 हजार करोड़ जारी किए

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी (माल एवं सेवा कर) राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके। क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रुपये जारी किये। यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है।

बयान में कहा गया है कि सभी पात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए वित्त पोषण को लेकर सहमत हैं। मंत्रालय के अनुसार, महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिए तथा पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता को लेकर वित्त मंत्रालय ने ये रकम जारी किए हैं।

रद्द जीएसटी पंजीयन बहाली पर जल्द फैसला

रिटर्न न दाखिल कर पाने की वजह से रद्द हो चुके जीएसटी अकाउंट के पंजीयन बहाली किए जाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक करीब आठ लाख से ज्यादा ऐसे कारोबारी हैं जिनका पंजीयन इन वजहों से रद्द हो चुका है और ये कारोबारी मौजूदा नियमों के तहत इस दिशा में चलाई जा रही एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। 16 कर विशेषज्ञों ने वित्तमंत्री से दखल देने की मांग की है।

वृद्धि दर दहाई अंक में रहेगी

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्यों द्वारा स्थानीय प्रतिबंधों को हटाने के चलते आर्थिक सुधार ने गति पकड़ी है, लेकिन यह अभी भी 2019 के स्तर से पीछे है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के निचले आधार के मुकाबले अप्रैल-जून 2021 के दौरान दहाई अंक में बढ़ेगी, लेकिन अभी भी यह वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में देखे गए स्तर से कम रहेगी।

देश में घरों की बिक्री 67% बढ़ी

नई दिल्ली। नाइट फ्रैंक इंडिया ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद इस साल जनवरी से जून के बीच आठ शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 99,416 इकाई हो गई। इनमें से मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा फ्लैट बिके।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के आठ बड़े शहरों में 2021 कैलेंडर वर्ष (एच1 2021) की पहली छमाही में 99,416 आवासीय इकाइयां बेची गईं।

बिजनेस आपतक

जोमैटो आईपीओ को 4.8 गुना अभिदान

नई दिल्ली। जोमैटो के 9,375 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को बिक्री के लिए रखे जाने के दूसरे दिन गुरुवार को 4.8 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ क्योंकि खुदरा निवेशकों की ओर से लगातार बोलियां लगाई जा रही हैं।

फ्रैंकलिन मामले में सेबी-सैट में ठनी

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने फ्रैंकलिन टेंपलटन मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के 28 जून के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। सैट ने अपने आदेश में सेबी के निर्देश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में तेजी

नई दिल्ली। रियल एस्टेट में सुधार को देखते हुए सोमानी सिरेमिक्स ने चार नए शोरूम खोले हैं। देश में उसके कुल शोरूम की संख्या बढ़कर 374 हो गई है। कंपनी ने दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ और शाहजहांपुर में नया स्टोर खोला है।

लैम्बॉर्गिनी ने उतारी 4.99 करोड़ की कार

नई दिल्ली। लैम्बॉर्गिनी ने भारत में ह्यूराकैन एसटीओ मॉडल पेश किया, जिसकी शोरूम कीमत 4.99 करोड़ रुपये है। कंपनी को इस साल ह्यूराकैन की दस से अधिक इकाइयां बिकने की उम्मीद है। इसमें 640 एचपी का इंजन है।

एचपी ने पेश किया एआई सॉल्यूशन

नई दिल्ली। एचपी इंडिया गुरुवार को छात्रों और शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित नया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पेश किया। यह डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन शिक्षण संस्थानों को डिजिटल लर्निंग के परिवेश के हिसाब से ढलने में मदद करेगा।

निर्यात 48% की वृद्धि के साथ 32.5 अरब डॉलर पर

मुंबई | एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्नों एवं आभूषणों, रसायनों, चमड़े और समुद्री वस्तुओं के निर्यात में अच्छी वृद्धि के कारण जून में देश का निर्यात 48.34 प्रतिशत बढ़कर 32.5 अरब डॉलर हो गया।

जून में आयात भी 98.31 प्रतिशत बढ़कर 41.87 अरब डॉलर हो गया।

आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान आयात बढ़कर 126.15 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 60.44 अरब डॉलर था। इस तिमाही में व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2020 के 9.12 अरब डॉलर के मुकाबले 30.75 अरब डॉलर रहा।

व्यापार घाटा 9.37 अरब डॉलर

इसके साथ व्यापार घाटा 9.37 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में व्यापार 0.79 अरब डॉलर अधिशेष में था। वाणिज्यक निर्यात के बादले आयात अधिक होने की स्थिति को व्यापार-घाटे की स्थिति कहा जाता है। अप्रैल-जून 2021 के दौरान, निर्यात 85.88 प्रतिशत बढ़कर 95.39 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-जून 2021 के दौरान, तेल आयात पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 13.08 अरब डॉलर के मुकाबले 31 अरब डॉलर रहा।

जून 2021 में खनिज तेल आयात 10.68 अरब डॉलर का रहा, जो जून 2020 के 4.93 अरब डॉलर की तुलना में 116.51 प्रतिशत अधिक था।

वित्तीय समावेशन प्राथमिकता में: दास

मुंबई | एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि महामारी के बाद परिस्थितिकीय अनुकूल बनाने के लिए वित्तीय समावेशन उसकी नीतिगत प्राथमिकता में बना रहेगा। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी इससे वंचित हैं।

दास ने एक शिखर सम्मेलन में कहा कि रिजर्व बैंक जल्दी ही पहला वित्तीय समावेश सूचकांक जारी करेगा। यह पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के मामले में प्रगति का आकलन करेगा। आरबीआई गवर्नर के अनुसार यह सुनिश्चित करने की सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वित्तीय परिवेश(डिजिटल माध्यम सहित) समावेशी हो। साथ यह उचित वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से गलत तरीके से बिक्री, साइबर सुरक्षा, आंकड़ा गोपनीयता जैसे जोखिमों को प्रभावी तरीके से दूर करने एवं और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम हो। लोगों तक बैंक की पहुंच सुनिश्चित कर अर्थव्यवस्था को संगठित रूप देने में मदद के लिए पिछले दशक की शुरूआत से वित्तीय समावेश पर आरबीआई का विशेष जोर रहा है। प्रौद्योगिकी ने इसे आसान बनाया और सरकार ने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरूआत कर इस पर काफी जोर दिया।

जीडीपी अनुमान घटाने की कोई वजह नहीं

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाने की कोई वजह नहीं है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। दास ने कहा कि टिकाऊ आर्थिक ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूजन बेहद महत्वपूर्ण है। यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में मदद करता है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत के जीडीपी अनुमान को घटाया है। हालांकि, कई एजेंसियों ने अपने अनुमान को बरकरार भी रखा है।

79% लोग मानते हैं कि इस साल उनकी आय घटेगी

नई दिल्ली | एजेंसी

देश के 79 फीसदी लोग मानते हैं कि इस साल उनकी आय घटेगी। यह जानकारी लोकल सर्किल की ताजा सर्वे रिपोर्ट से मिली है।

सर्वे के अनुसार, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ी महंगाई ने जकड़ लिया है। पेट्रोल-डीजल समेत खाने-पीने के सामान की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इससे उनका बजट बिगड़ रहा है।

सर्वे में शामिल 65 फीसदी परिवारों का कहना है कि बीते चार महीने में सब्जियों के दाम 25% से 100 फीसदी तक बढ़े हैं। सर्वे में शामिल 32% लोगों का कहना है कि उनकी आय 25% या अधिक घटेगी। वहीं, 12% लोगों का मनना है कि उनकी आय में 10% से 25% की कमी आएगी।

10% लोगों को लगता है कि आय में 10 % तक गिरावट आ सकती है। वहीं, 25% लोगों का कहना है कि आय गिरेगी लेकिन कितना यह नहीं कह सकते हैं जबकि 17% लोगों को लगता है कि उनकी आय पर कोई असर नहीं होगा। बचत को 19 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि 25प्रतिशत तक घटेगी।

सर्वे

- 32% लोगों का कहना है कि उनकी आय 25% या अधिक घटेगी
- 12% लोगों का मनना है कि उनकी आय 10% से 25% घटेगी

पेंशनरों को पर्ची व्हाट्सएप पर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि बैंक खाते में रकम आने पर वे एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर पेंशनधारकों को उनकी पेंशन पर्ची भेज सकते हैं। एक आधिकारिक आदेश में यह बात कही गई है।

आदेश के अनुसार पेंशनधारकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक, एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पेट्रोल- डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी

नई दिल्ली | एजेंसी

पेट्रोल की कीमतों में गुरुवार को 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद देश भर में कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 101.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर है। कीमतों में तीन दिनों के बाद बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में आखिरी बार 12 जुलाई को बढ़ोतरी हुई थी, और इस दिन डीजल की कीमतों में लगभग तीन महीने में पहली कमी की गई। डीजल के दाम में हुई ताजा बढ़ोतरी ने 12 जुलाई को हुई 16 पैसे की कमी को बेअसर कर दिया। पेट्रोल के दाम में चार मई के बाद से 40 बार बढ़ोतरी हुई है।

बोझ

- पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा
- दिल्ली में पेट्रोल 101.54 रुपये प्रति लीटर पहुंचा

सेंसेक्स 255 अंक बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंचा

मुंबई | एजेंसी

बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 255 अंक उछलकर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। कंपनियों के बेहतर वित्तीय परिणाम के संकेत के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी और एचसीएल टेक में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई।

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 254.75 अंक उछलकर रिकार्ड 53,158.85 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान भी यह अबतक के उच्चतम स्तर 53,266.12 अंक तक चला गया था। एनएसई का निफ्टी70 अंक की तेजी के साथ अबतक के सर्वोच्च स्तर 15,924 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 15,952.35 के रिकार्ड ऊंचाई तक गया था।

उछाल

- बीएसई सेंसेक्स 53,158.85 अंक पर बंद हुआ
- निफ्टी 70 अंक बढ़कर 15924 अंक पर बंद

सोने और चांदी के दामों में तेजी

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं में तेजी के अनुरूप दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 177 रुपये की तेजी के साथ 47,443 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,266 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी भी 83 रुपये की तेजी के साथ 68,277 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का 68,194 रुपये प्रति किलो थी।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,831 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

मकान किराए पर कर छूट का लाभ लें

काम की खबर

नई दिल्ली | रेणु यादव

आमतौर पर माना जाता है कि मकान का किराया भत्ता (एचआरए) मिलने पर ही आयकर छूट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं है और चुकाए गए किराए पर कर छूट का लाभ ले सकते हैं। आयकर की धारा 80जीजी के तहत सालाना 60 हजार रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं जिसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जिनको पूरी करनी होंगी।

कैसे कर सकते हैं दावा : विशेषज्ञों के मुताबिक इस छूट का दावा करने के लिए करदाता को फॉर्म 10बीए भरना होता है। यह एक स्वघोषणा पत्र होता है जिसमें स्पष्टीकरण दिया जाता है कि आपने एचआरए के तहत कोई क्लेम नहीं किया है।

कब मिलती है किराया भत्ता पर आयकर छूट

चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े का कहना है कि यह छूट तभी मिलेगी जब कंपनी आपको सैलरी में एचआरए का अलग से विवरण न देती है। वहीं जिस शहर में आपकी नौकरी या कारोबार है वहां आपका या पत्नी या बच्चों के नाम से या हिन्दु अविभाजित परिवार के नियम के तहत कोई मकान नहीं हो।

mint

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना: ई-निविदा संख्या- 04/2021-22/E.D.C./GZB, निविदा शुल्क: रु. 1180.00, धरोहर धनराशि: 2000.00, कार्य का विवरण: विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर के क्षेत्रान्तर्गत कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु लाइनों की मरम्मत करना, शाटिंग करना, रिसैगिंग करना एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पोलों पर 5 फीट की ऊँचाई तक प्लास्टिक की पतली शीट/इन्सुलेटिड सामग्री लगाना एवं परिवर्तकों के चारों ओर बेरिकेटिंग करने इत्यादि का कार्य। ई-निविदा संख्या- 05/2021-22/E.D.C./GZB, निविदा शुल्क: रु. 1180.00, धरोहर धनराशि: 2000.00, कार्य का विवरण: विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर के क्षेत्रान्तर्गत कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु लाइनों की मरम्मत करना, शाटिंग करना, रिसैगिंग करना एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पोलों पर 5 फीट की ऊँचाई तक प्लास्टिक की पतली शीट/इन्सुलेटिड सामग्री लगाना एवं परिवर्तकों के चारों ओर बेरिकेटिंग करने इत्यादि का कार्य। उपरोक्त कार्य बाह्य एजेंसी के माध्यम से कराने हेतु अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की गई है, जिसे https://etender.up.nic.in पर दिनांक 22.07.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक भरा जा सकता है तथा दिनांक 22.07.2021 को दोपहर 16.00 बजे एवं उसके पश्चात खोला जाएगा। निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 0180002100028563 (IFSC- PUNB0018000) में पृथक रूप से जमा कराकर बैंक जमा का साक्ष्य यथा योग्य यू.टी.आर. सं. पे-इन-स्लिप की प्रति अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ निविदा के प्रथम भाग में अपलोड किया जाना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए समस्त अथवा किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। कार्य की कुल मात्रा, निविदा विशिष्टीकरण व अन्य नियम एवं शर्तें अथवा निर्धारित तिथि के विस्तार तथा शुद्धिपत्र से सम्बन्धित सूचना केवल निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org तथा https://etender.up.nic.in पर डाली जाएगी। अतः स्वयं को अपडेट रखने के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित देखें। अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद। "राष्ट्र हित में बिजली बचायें"। विद्युत हेल्पलाइन 1800-180-3002 (मेरठ), 1800-180-8752 (लखनऊ)। पत्रांक: 551/वि.वि.मं./गा.बाद/ दिनांक:15.07.2021

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, पीसीएमएम/आरसीएफ द्वारा निम्नलिखित मदों के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	निविदा सं./नियत तिथि	विवरण	मात्रा	ईएमडी (रु.)
1.	112211199/09.08.2021	[illegible]	245 सेट	83,490/-
2.	12211187/06.08.2021	[illegible]	41 नग 41 नग	53,340/-
3.	13206260डी/09.08.2021	[illegible]	34 नग	00
4.	17211395/09.08.2021	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]	20 सेट्स 12 सेट्स 146 सेट्स 40 सेट्स 69 सेट्स	20,00,000/-
5.	01211134?/06.08.2021	[illegible]	1. 100 नग 2. 62 नग 3. 58 नग	20,00,000/-
6.	01211169/13.08.2021	[illegible]	7300 नग	0

1. विवरण और ऑनलाइन निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए, वेबसाइट http://ireps.gov.in पर जाएं। [illegible] http://www.rcf.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन बोली देने हेतु [illegible] http://www.cca.gov.in [illegible] 2. बोलियां निर्धारित तिथि को 14.25 बजे बंद होंगी तथा 14.30 बजे खोली जाएंगी। [illegible] 3. [illegible] 011-24102855, 011-24105180 [illegible] 011-23378658 में।

टिप्पणी: आरसीएफ का जीएसटी नम्बर 03AAAGM0289C1ZT है। [illegible]

पीसीएमएम

शुद्धिपत्र

[illegible] 1. 07211376 [illegible], 2. 07211387 [illegible], 3. 07211391 [illegible], 4. 07211393 [illegible], 5. 07211398 [illegible], 6. 07211402 [illegible] 13.07.2021, इस प्रकार पढ़ा जाये: 20.07.2021

पीसीएमएम

टी.नं. जी-आरसीएफ/122-01/स्टोर्स/039/2021-22 दिनांक: 15.07.2021

सशस्त्र सीमा बल

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशक

खंड-V (पूर्वी), रा.कृ.पुरम, नई दिल्ली-110066

फोन नं0 011-26104291, www.ssbrectt.gov.in

एस.एस.बी. में विभिन्न भर्तियों के लिए पी.ई.टी. के दौरान आर.एफ.आई.डी. प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, पी.एस.टी. में स्वचालित मशीन का इस्तेमाल करने, भर्ती कार्यकलापों के दौरान बायोमैट्रिक कैपचरिंग और वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज करने के कार्य हेतु रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) उन प्रख्यात फर्मों या एजेंसियों से ई.ओ.आई. आमंत्रित करता है जो राज्य पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के भर्ती बोर्डों के लिए पीईटी के दौरान आर.एफ.आई.डी. प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, पी.एस.टी. में स्वचालित मशीन का इस्तेमाल करने, भर्ती कार्यकलापों के दौरान बायोमैट्रिक कैपचरिंग और वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं।

पूर्व-योग्यता मानदंड अधोलिखित अनुसार हैं:-

(i) फर्म के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र और मेमोरेण्डम/एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स की प्रतियां होनी चाहिए।

(ii) फर्म आईएसओ/आईएसएमएस प्रमाणित कम्पनी/फर्म होनी चाहिए।

(iii) फर्म के पास जीएसटी नम्बर होना चाहिए।

(iv) फर्म का विगत 5 वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष 2 करोड़ का न्यूनतम औसत कारोबार होना चाहिए।

(v) फर्म के पास एक साथ कम-से-कम 10 स्थानों में कम से कम 15 दिनों की अवधि के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान भारत में कम-से-कम 5 प्रख्यात ग्राहकों/भर्ती बोर्डों के लिए भर्ती कार्यकलापों के दौरान, 2,00,000 से अधिक उम्मीदवारों हेतु पी.ई.टी. के दौरान आर.एफ.आई.डी. प्रौद्योगिकी के उपयोग, 50,000 से अधिक उम्मीदवारों हेतु पी.एस.टी. में स्वचालित मशीन के इस्तेमाल, 2,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए बायोमैट्रिक कैपचरिंग और वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज के कार्य को निष्पादित करने का अनुभव हो। (संतुष्टिपूर्वक कार्य समापन प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं)।

(vi) फर्म देश भर में 10 स्थलों में पीईटी/पीएसटी, बायोमैट्रिक प्रमाणन, वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज को आयोजित करने हेतु संसाधनों - श्रम, हार्डवेयर, नेटवर्किंग व इंटिग्रेटिड सॉफ्टवेयर तक पहुंच साबित करने में सक्षम होनी चाहिए।

(vii) फर्म को कार्य-आदेश प्रदान करने तक, न तो किसी सरकारी/क्षेत्र संगठन द्वारा कालीसूचीकृत किया गया हो और न ही अकार्यप्रदर्शन/प्रौद्योगिकी की असफलता के कारण उनके अनुबंध/कार्य-आदेश को निरस्त किया गया हो।

(viii) फर्म का मुख्यालय भारत में होना चाहिए।

(x) रुचि की अभिव्यक्ति हेतु उनके पत्रों के साथ प्रदान दिए नए समर्थित दस्तवेजों के आधार पर पात्र पाई गई फर्मों को विस्तृत गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यूआर) की आपूर्ति की जाएगी।

(x) पात्र फर्मों को कार्य-योजना और कार्यान्वयन रूपरेखा के साथ पीईटी/पीएसटी संचालित करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की पावर प्वाइंट प्रस्तुति पेश करनी होगी।

(ix) पात्रता मानदंड पूरा करने वाली फर्मों को अपनी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी सूचना पृथक रूप से भेजी जाएगी।

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली इच्छुक फर्में, समाचारपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर **adrectt.ssbdel@nic.in** में कमाण्डेंट (भर्ती), एफएचक्यू, एसएसबी, खंड-V (पूर्वी), रा.कृ. पुरम, नई दिल्ली-110066 को समर्थित दस्तवेजों के साथ अपनी रुचि की अभिव्यक्ति अग्रप्रेषित करें।

कमाण्डेंट (भर्ती)

डी.ए.वी.पी. 19114/11/0003/2122 **एफ.एच.क्यू, एसएसबी, नई दिल्ली**